Seventeenth Loksabha

an>

Title:Regarding Andhra Pradesh Disha Act,2019

श्रीमती चिंता अनुराधा (अमलापुरम): सर, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने ए.पी. दिशा विधेयक, 2019 को पारित किया है। यह विधेयक एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य सात दिनों के भीतर जांच पूरी करना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का 14 दिनों के भीतर परीक्षण करना है। ऐसे मामलों में विधेयक त्वरित न्याय और कड़ी सजा के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

आंध्र प्रदेश राज्य ने 18 आईएसओ प्रमाणित दिशा महिला पुलिस स्टेशनों के संदर्भ में एक सक्षम ढांचे की स्थापना के लिए सक्रिय कार्रवाई की है। पीड़ितों के मनो-सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 700 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, 13 वन स्टॉप सेंटर, 12 नामित महिला अदालतों और 9 विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की गई है। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दो-दो आईएएस और आईपीएस अधिकारी विशेष रूप से तैनात हैं। दिशा ऐप संकट में महिलाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का व्यापक रूप से 19.83 लाख डाउनलोड के साथ उपयोग किया गया है। चूंकि आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया और प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप राष्ट्रपति के विचार और सहमति के अधीन हैं। मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जिसने इसे आगे परामर्श के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया है। चूंकि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अपनी सिफारिशों के साथ वापस आ गया है। इसलिए, मैं गृह मंत्री से आंध्र प्रदेश में एक मजबूत और प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए मामले में तेजी लाने का आग्रह करती हूँ।